Supply of fruits and vegetables to major Cities

2448. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any efforts have been made by Government to supply fruits and vegetables in large quantity in view of their increasing demand in the cities in the country like Delhi, Jaipur, Bhubaneshwar, Mumbai and Calcutta;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the rates of fruits and vegetables have almost doubled in these cities; and

(d) if so, what efforts, till date, have been made by Government to reduce the price and increase the production of fruits and vegetables?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Due to steep rise in prices of onion during January-February, 1998, the Government of India through National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) arranged the sale of onion at resonable price in 3 major cities *i.e.* Delhi, Chennai and Hyderabad. NAFED has distributed 1,777 metric tonnes of onion during 2nd January, 1998 to 21st February, 1998.

(c) Due to seasonal variations, the rates of fruits and vegetables are fluctuating in various markets of the country. Fruits like apple, citrus, banana, etc. and vegetables like potato, onion, tomato, etc. have shown rising trend during last few weeks.

(d) For increasing the production of fruits and vegetables and subsequently increasing the supply, the Government of India is promoting the schemes on fruits and vegetables namely (i) Integrated Development of Tropical, Arid & Temperate Zone Fruits, (ii) Production and Supply of Vegetable Seeds, and (iii) Development of Root & Tuber Crops in the country. The Government of India through National Horticulture Board (NHB), National Cooperative Development Corporation (NCDC) is also providing financial assistance for creating infrastructure facilities for cold storage, packing and grading centres for better marketing facilities which would help enhanced and timely supply of fruits and vegetables and control the prices.

तिलहन उत्पादन

2449. **श्रीमती शबाना आज़मी:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1998 को दैनिक ओब्जर्वर में "आयल सीड्स आउटपुट पोटेंशियल सीन एट 49-70 मि॰ टन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में तिलहन उत्पादन की क्षमता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो आंकी गई मात्रा कितनी है और वर्तमान उत्पादन इससे कितना कम है; और

(घ) आंकी गई मात्रा से कम उत्पादन होने के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में तिलहन उत्पादन की क्षमता का कोई आकलन नहीं किया गया है क्योंकि इसके लिए तिलहन फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र, मण्डी मूल्य, अन्तः फसल लाभकारिता, किसानों के आर्थिक निर्णय तथा मौसम की स्थिति जैसे कई कारक शामिल हैं। फिर भी, 8 कि॰ ग्रा॰ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से खाद्य तेलों की नियामक मांग के आधार पर खपत की आवश्यकता का आकलन किया गया है तथा तदनुसार, योजना आयोग द्वारा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1998-99 के लिए तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 270 लाख मी॰ टन निर्धारित किया गया है।

(घ) भारत में तिलहन के कम उत्पादन के कारण मुख्यतः बीजों, उर्वरकों, कीटनाशियों और सिंचाई जैसे अधिक गुणवत्ता वाले आदानों पर कम निवेश क्षमता वाले छोटे और सीमांत किसानों द्वारा वर्षा सिंचित परिस्थितियों में इनकी खेती करना तथा मौसम की

असामान्यताओं तथा कीटों और रोगों के हमले में इन फसलों की संवेदनशीलता है।

Import of black gram

2450. SHRI YADLAPATI VENTKAT RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether black gram is being imported from countries like Burma etc.;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that the black gram prices are dipped down to 900 rupees per quintal after import;

(d) the prices of imported black gram; and

(e) what are the steps taken to ensure remunerative price to farmers for black gram?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The Government resorts to improt of pulses to bridge the gap between demand and supply.

(c) The current wholesale prices of black gram at selected centres of the country are ruling in the range of Rs. 1075-1850 per quintal.

(d) As per the latest available information, the average price of black gram imported from Myanmar during April-July, 1997 worked out to Rs. 1225 per quintal.

(e) The Government fixes minimum support prices of major agricultural commodities including black gram. The National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) is the central nodal agency for undertaking price support operations in respect of pulses including black gram.

मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमतों में गिरावट

2451. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमतों में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण केन्द्रों पर गेहूं के थोक मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक हैं। इन चुनिंदा केन्द्रों में गेहूं वर्तमान थोक मूल्य 540 रुपये प्रति क्विंटल से 800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है।

(ग) मूल्य समर्थन संबंधी कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि किसानों को अपने उत्पादन मजबूरी में बेचने न पड़ें। देश भर में खरीद केन्द्रों का एक तन्त्र स्थापित किया जाता है तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसका विस्तार भी किया जाता है। प्रत्येक विपणन मौसम के आरम्भ होने पर पहले ही खरीद के प्रबंध कर लिए जाते हैं।

World Bank's Assistance to Karnataka

2452. SHRI S.M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the amount of assistance provided by World Bank to Karnataka under National Agricultural Extension Projects;

(b) whether government have made a review of the effect on these projects due to recently imposed sanctions;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The World Bank assistance provided to Karnataka under National Agricultural Extension Project